अरावली में मची लूटखसोट को दबाने के लिए हरियाणा सरकार नंगी हुई

अरावली में 52 एकड़ क्षेत्र को वन घोषित किया जाए, एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ खट्टर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: अरावली को जब कोई सरकार ही बर्बाद करने पर तुल जाए तो न्याय व्यवस्था ही क्या कर लेगी। अरावली की लूट में अब हरियाणा सरकार खुल कर सामने आ गई है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा अरावली की 52 एकड़ जमीन को फॉरेस्ट यानी वन घोषित करने पर हरियाणा सरकार बौखला गई और एनजीटी के फैसले को उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार (18 जुलाई) को इस मामले की सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में एनजीटी के आदेश को गलत, एकतरफा, मनमाना और इसके अलावा भी कई घटिया शब्दों नवाजा है।

हमारी पड़ताल बता रही है कि दरअसल इसकी आड़ में योगी ठग गुरु द्वारा अरावली में खरीदी गई जमीनों को बचाने के लिए यह सब कवायद की गई है। बहुत साफ-साफ दिख रहा है कि अगर अरावली के गांवों में रह रहे लोग, अरावली के पर्यावरण से सरोकार रखने वाले लोग न जागे तो पूरे अरावली में जंगल खत्म हो जाएंगे।

भारती लैंड ने पेड़ काट डाले

यह 52 एकड़ जमीन सराय ख्वाजा इलाके के तहत अरावली में आती है। भारती लैंड लिमिटेड ने इस जंगल को अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए खरीद लिया। जाहिर सी बात है कि यह जमीन हरियाणा सरकार ने ही बेची होगी, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हूडा) ने जहां सेक्टर 43 बना रखा है, उसी के पास यह जमीन है। इस इलाके की जमीन पर हरियाणा वन विभाग शुरू से अपना दावा जताता रहा है। उसका कहना था कि यह पूरा इलाका फॉरेस्ट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले मंत्रालय के क्षेत्रीय दफ्तर ने भी इसे फॉरेस्ट लैंड बताया। दरअसल, हरियाणा सरकार ने खुद ही अरावली की 50 हजार एकड़ जमीन को वन घोषित कर रखा है।

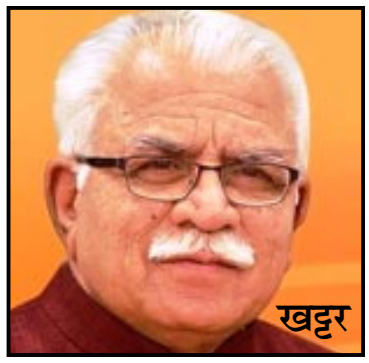

लेकिन इस 52 एकड़ फॉरेस्ट को अचानक हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपनी इज्जत बना लिया। भारती लैंड ने 2017 में करीब सात हजार पेड़ अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काट डाले। इसके बाद ही पर्यावरणवादियों की इस पर नजर गई और सारा मामला एनजीटी तक जा पहुंचा।

ठग गुरु की नजर अरावली पर

ठग गुरु के समूह ने अरावली क्षेत्र में 400 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है। छानबीन से पता चला है कि फॉरेस्ट लैंड के बड़े हिस्से का लेन-देन 2014 से 2016 के बीच हुआ था। हरियाणा पंचायत और वन कानून के मुताबिक नियमानुसार ये ज़मीनें अधिग्रहित नहीं की जा सकती हैं। इस अधिग्रहित 400 एकड़ में से अधिकतर ज़मीन 'गैर मुमकिन पहाड़' या 'शामलात देह' की है। गैर मुमकिन पहाड़ वह ज़मीन होती है जिस पर न तो खेती-किसानी, न व्यवसाय और न ही किसी को कब्ज़ा दिया जा सकता है। शामलात देह गांव की साझा ज़मीन होती है जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होती है और जिसे किसी व्यक्ति या कंपनी को बेचा नहीं जा सकता है।

हरियाणा विधानसभा ने फ़रवरी 2019 में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1990 में संशोधन किया, जिससे अरावली पर्वत श्रृंखला में रियल एस्टेट के विकास और खनन के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण का रास्ता साफ़ हो सके। सरकार के इस फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जंगल को तबाह करने की कोशिश करने के लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन दरअसल यह कानून भी ठग गुरु की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया। हालांकि मीडिया में 400 एकड़ जमीन की बात ही आई है लेकिन पता चला है कि ओमेक्स और कुछ पार्टनरों के साथ भी मिलकर अरावली और अन्य जगहों पर ठग गुरु ने जमीनें खरीदी हैं। पिछले दिनों ओमेक्स के एक पार्टनर के हाउसिंग प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में खुद ठग गुरु शामिल हुआ था। दरअसल, ठग गुरु के आने का मकसद यही था कि इन सारे प्रोजेक्ट को ठग गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर ठग गुरु साथ है तो समझो हरियाणा सरकार साथ है, क्योंकि ठग गुरु हरियाणा सरकार का ब्रैंड एम्बैसडर है।

बहुत बड़ा स्कैम, दूर से छोटा

अरावली में जमीन लूटने का स्कैम बहुत बड़ा है। एनजीटी ने अभी सिर्फ 52 एकड़ जमीन को फॉरेस्ट मानकर अपना फैसला सुनाया है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को या उसके बाद एनजीटी के फैसले पर मुहर लगाता है तो कई और लोग याचिका दायर कर इस अरावली की लूट को बेनकाब कर सकते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने बहुत सोचसमझकर 52 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को सामान्य जमीन साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ठग गुरु की जमीन का मामला पहले से ही अदालत पहुंचा हुआ है। इस तरह दूर से अरावली का छोटा लगने वाला स्कैम बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद स्थितियां और भी साफ होंगी। अरावली में खनन संपदा की लूट पहले यहां के माफियाओं ने की और रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। अरावली में पानी नहीं है, इसके बावजूद वहां हरियाणा सरकार अपार्टमेंट बनाने, मॉल बनाने आदि के लाइसेंस, लैंड यूज चेंज के आदेश धड़ल्ले से जारी कर रही है। अरावली में आप जिस तरफ निकलेंगे, वहां आपको पक्के मकान या अपार्टमेंट नजर आएंगे। इनका निर्माण दो चार दिन में नहीं हुआ है।

पाठकों को याद होगा कि हरियाणा सरकार और भाजपा ने 2014 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों का जोरशोर से प्रचार किया था। सत्ता मिलते ही मनोहर लाल खट्टर सरकार ने वाड्रा के खिलाफ जमीन के मामलों में कई एफआईआर दर्ज कराई। जस्टिस ढींगरा आयोग सिर्फ वाड्रा की जमीनों की जांच के लिए बनाया। उस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी खट्टर सरकार को सौंप दी। जिसमें साफ तौर पर जमीन के लिए वाड्रा द्वारा मचाई गई लूट खसोट का जिक्र है। हरियाणा सरकार ने अभी तक वह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की और न ही उस पर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश की। खट्टर सरकार अपने पांच साल पूरा करने जा रही है लेकिन वाड्रा या कोई बड़ा कांग्रेसी नेता जमीन के लूट खसोट मामले में अभी तक अंदर नहीं गया।

जागने का समय

अरावली पर नेताओं, ठग गुरुओं, धंधेबाजों की नजर हमेशा से रही है। अस्सी के दशक में जब भजनलाल की सरकार थी तो उस समय एक बाल्टी बाबा फिरता था। उसने अरावली में डिजनी लैंड बनाने की महत्वाकांक्षा पेश की। भजनलाल उसके झांसे में आ गए। लेकिन उस समय अरावली के गांवों में रहने वाले गुर्जरों ने और उस समय ब्लिट्ज अखबार के पत्रकार रहे यूसुफ किरमानी ने इस मामले को जमकर उछाला। गुर्जरों के आंदोलन के आगे तत्कालीन भजनलाल सरकार को झुकना पड़ा और बाल्टी बाबा भी फरीदाबाद से भाग खड़ा हुआ। हालांकि बाद में भजनलाल को सिद्धदाता आश्रम ने लपक लिया और अरावली में मंदिर और आश्रम बनाने के लिए जमीन हथिया ली।

लेकिन अरावली को अब जिस तरह उजाड़ने की साजिश रची जा रही है, उसे देखते हुए तमाम पर्यावरणवादियों और फरीदाबाद के लोगों को एक मंच पर आकर सरकार की करतूतों को उसका जवाब देना चाहिए। अगर अब भी नहीं जागे तो अरावली की पहाड़ियां नंगी हो जाएंगी। राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली रेतीली हवाएं इस इलाके को मरुस्थल बनाने में देर नहीं लगाएंगी। हरियाणा विधानसभा का चुनाव नजदीक है, क्या फरीदाबाद की जनता अरावली को मुद्दा बनाना चाहेगी...सोचिए।

बजट-2019 ग़रीबों के लिये जुमले-अमीरों के लिये गुलगुले

अजात शत्रु

वैसे तो पिछले कई सालों से ही बजट में लेखा-जोखा कम और बातें ज्यादा होती रही हैं। जेटली साहब इस बारे में कुछ शालीन थे लेकिन नयी वित्त मंत्री ने तो अपने पहले ही बजट में आते ही घूंघट ही उतार फेंका। पूरा बजट पढो तो खर्चे और आमदनी का लेखा-जोखा कम और वादों और जुमलों की किताब ज्यादा लगा। ऐसा लगा जैसे अगले चुनाव के लिये लोग़ों को बहकाने के लिये भाषण दिया जा रहा हो। शुरू के आधे भाषण में तो सिर्फ़ भविष्य के सुनहरी सपने दिखाने, शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव पकाने के अलावा कुछ नहीं। शेष आधे में भी सटीक जानकारी देने से बचने की कोशिश नज़र आयी। लेकिन जितना मजबुरीवश वित्तमंत्री जी ने बताया उससे लगता है कि गरीब जनता को उल्लू बनने के अलावा कुछ हाथ नहीं आया।

बजट की शुरूआत दस साला कार्यक्रम और भारत की अर्थव्यवस्था को अगले पांच साल में 50 खरब यानी 5000 अरब डालर (यानी 330000 करोड़ रुपये) तक पहुंचाने की बात की गई है। ये अलग बात है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन जायेगी न तो बजट में इसका विवरण है और न ही इस बात का कि भारत के सबसे गरीब लोग़ों को इसका कितना लाभ मिलेगा। दस साला कार्यक्रम में भी लोग़ों को पानी बचाने पेड़ लगाने की नसीहत ही दी गयी है। यानी पहले लोग़ों को स्वच्छता का झुनझुना पकड़ा कर पांच साल काट दिये और अब पेड़ लगाओं पानी बचाओ का लालीपाप थमा दिया। यानी खुद कुछ करना नहीं लोग़ों को ही जिम्मेदार ठहराना उनकी परेशानियों के लिये। न देश में पिछले पांच साल से कोई सफ़ाई हुई और न अगले दस साल में पेड़ बढने जा रहे हैं। क्योंकि जितने छोटे पौधे लगाये जायेंगे उससे कई गुना ज्यादा तो गडकरी जी अपने रोड प्रोजेक्ट्स के लिये बड़े पेड़ काट फ़केंगे। एक मोटे अनुमान के अनुसार राजमार्ग मंत्रालय अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिये इस साल लगभग सवा करोड़ बड़े पेड़ काट फेंकेगा। इनमें ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी देश के विकास के लिये कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ़ धर्म के नाम पर लोग़ों को उल्लू बना कर वोट लेने के लिये हैं जैसे कि चार धाम यात्रा का चार लेन का रोड, रामायण सर्किट, काशी सर्किट आदि।

किसी देश के विकास के लिये सबसे जरूरी क्षेत्र शिक्षा में बजट में वास्तव में कटौती की गयी है। बजट में इसके नाम पर सिर्फ बकौती है। रिसर्च की बात है लेकिन उसके लिये धन नहीं है यानी धन सब शिक्षा संस्थानों ने खुद ही जुगाड़ना है। ग़रीबों के लिये पढाई के दरवाजे लगभग बंद हो जायेंगे विशेषकर उच्च शिक्षा के लिये। इसके अलावा बाहर से आने वाली किताबों पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाने का काम भी पहली बार किसी सरकार ने किया है। बाहर से आने वालो अखबारों के कागज पर भी टैक्स बढा दिया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य के नाम पर भी आयुष्मान भारत का झुनझुना है जिसके बजट में दिल्ली के ही सारे लोग़ों का इलाज नहीं हो सकता।

बजट में सबसे ज्यादा जोर सरकारी कंपनियों को बेचकर धन उगाहने पर है। इस साल लगभग 18 सरकारी कंपनियां बेचकर एक लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार जमा करेगी। इनमें बीएसएनएल जैसी कंपनियां है जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपये की सम्पत्तियां है जिनको कुछ सौ करोड़ में अम्बानी जैसों को बेचने के षडयन्त्र रचे जा रहे हैं। बड़े हैरानी की बात है कि इस देश में हर ग़रीब और मध्यम वर्ग के आदमी को नौकरी तो सरकारी चाहिये और वकालत वो सरकारी कंपनियों को प्राइवेट को बेचने की करता नज़र आयेगा।

इसके अलावा किसानों के लिये सिर्फ़ लफ्फ़ाजी है। न उनको ऋण मुक्त करने का कोई खाका बजट में है और न उनकी आय बढाने का। किसानों को 6000 रुपये प्रति माह देने का वादा करने पर चुनाव में कांग्रेस का मजाक उड़ाने वाली भाजपा दुकानदारों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना लायी है। यानी किसान प्रदर्शन करो, आत्महत्या करो तो भी कुछ नहीं और दुकानदार को घर बैठे पेंशन, वो भी 1.5 करोड़ सालाना तक की बिक्री करने वाले को भी। केपनियों पर भी सरकार मेहरबान हुई है। 400 करोड़ सालाना तक टर्न ओवर की कंपनियों को आयकर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे हमें 3000 करोड़ रुपये सालाना का चूना लगेगा। मज़दूरों की भी कमर तोड़ने की तैयारी की जायेगी। सारे श्रम कानूनों को इकट्ठा कर के चार कोड श्रम कानून लाये जायेंगे जो निश्चित रूप से, सरकार के रवैये को देखते हुये श्रमिक विरोधी होंगे।

इसके अलावा छिटपुट कहीं छूट तो कहीं टैक्स है। रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपये अपने ढांचे को ठीक करने में लगाने की सलाह दी गयी है। रेलवे कहां से ये पैसा लायेगी इस पर वित्तमंत्री ने मुंह नहीं खोला है। रेलवे को ग्रामीण इलाकों में भी रेल चलाने की नसीहत दी गयी है। सबके लिये सलाह बजट में बहुत है लेकिन सरकार क्या करेगी ये ज्यादातर गुप्त रखा गया है।

पिछले पांच साल में स्वच्छ भारत मिशन पूरा करने पर बजट में खुद अपनी पीठ थपथपा ली गयी है। करोड़ों शौचालय बनाने और खुले में शौच मुक्त भारत का दावा है लेकिन सच्चाई आप सब के सामने पूरे भारत में बिखरी पड़ी है। खुद एनजीटी ने उत्तराखंड के औली में गुप्ता बन्धुओं की बहुचर्चित शादी में मज़दूरों द्वारा खुले में शौच करने पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

बहुत सारी बातें और घूंघट की कोट से कही गई है जिनका वक्त आने पर खुलासा हो जायेगा। कुल मिलाकर बजट भाजपा की नीतियों के अनुरूप है। ग़रीबों को जूते मारो, अमीरों को हलवा दो, लेकिन प्रचार सिर्फ़ उन चन्द टुकड़ों का करो जो गरीबों को फेंके गये हैं। कुल मिलाकर किसान, मज़दूर और निम्न आय वर्ग की हालात और खराब होने जा रही है लेकिन इसके लिये अभी पांच साल और नेहरू और कांग्रेस ही जिम्मेदार बताये जायेंगे। बाकी या तो आप मुसलमानों और गाय पर चर्चा करो नहीं तो जूते मार कर आप को ठीक करने के लिये हर जगह गुंडावाहिनी तैयार है ही।

थोथा चना बाजे घना उर्फ़ अनिल विज

अजात शत्रु

हरियाणा में एक भाण्ड को मन्त्री बनाया हुआ है। नाम है अनिल विज। ये महाशय काम कम करते हैं और तमाशा ज्यादा करते हैं। उल्टे सीधे छिछले स्तर के बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं और इस के पीछे अपने निकम्मेपन को छिपाना चाहते हैं। इनके पास स्वास्थ्य विभाग है जिसके वारह बांट हुये पड़े हैं। लेकिन उसे छोड़ ये हर विभाग और हर बात के बारे में भांडो की तरह शोर मचाते रहते हैं।

10 जुलाई को न्यूजीलैण्ड से हारकर भारत क्रिकेट के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस पर पटाखे फ़ोड़ते जश्न मनाते कुछ युवकों का एक वीडियो भेजा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि यह कश्मीर का है और कश्मीरी युवकों ने भारत के हारने पर जश्न मनाया। इस पर अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि इनकी सब सुविधाएं बन्द कर देनी चाहिये। भूखे मरेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जायेगी। मन्त्री जी वो तो जब सरकार सुविधाएं बन्द करेगी तब मरेंगे (और पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे) पर आपके प्रदेश में तो स्वास्थ्य केन्द्रों की बदहाली के कारण लोग बेमौत मर रहे हैं। ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, टैस्ट के लिये मशीने नहीं और आप भाषण वीर बने घूमते रहते हो। एकाध जगह कोई डॉक्टर बचा हुआ है काम करने को तो उसे और सस्पेंड कर आते हो। अगर देशभक्ति का इतना जज्बा है तो देशवासियों का भी कुछ ख्याल कीजिये। बात-बात पर कश्मीरियों को गाली देते रहने से हरियाणावासियों की तकलीफ़ें कम नहीं होने वाली।

बता दें कि लाखनमाजरा पीएचसी में पीने का पानी तक घर से ले जाना पड़ता है। वही छारा पीएचसी की नयी बिल्डिंग करीब दो साल से बनकर तैयार है और स्टाफ़ के नाम पर वहां सिर्फ़ चौकीदार ही तैनात हैं। डॉक्टरों की तकरीबन आधी पोस्ट हरियाणा में खाली पड़ी हैं। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कान्ट्रेक्ट यानी ठेके पर डॉक्टर भर्ती करेंगे। जब आई ए एस और एचसीएस हर साल रेगुलर भर्ती कर लेते हो तो डॉक्टर क्यों नहीं रेगुलर भर्ती कर सकते। और एक गोली दे रहे हैं कि डॉक्टरी करने के बाद दो साल सरकारी नौकरी जरूरी करने का कानून लायेंगे। महोदय आप रेगुलर भती करिये, नौकरी करने वालों की तो लाइन लगी पड़ी है, कानून लाने की क्या जरूरत?

इससे पहले ये महाराज दो जगह के एसडीओ को सस्पेंड करने के आदेश दे चुके हैं। जिनमें से एक तो कोर्ट के आदेशों से बहाल होकर वापस आ गया और दूसरे पानीपत में 'हुडा' के एक एसडीओ और जेई को वहां की डीसी ने सस्पेंड करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अपने विभाग को व्यवस्थित करना तो गया भाड़ में दूसरों के शीशे और तोड़ आओ। सच है निकम्मा आदमी ही ज्यादा फूं-फ़ां करता है। थोथा चना बाजे घना।